AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

पंचायती राज प्रणाली की सफलता में डिजिटल उपकरणों की भूमिका

ORIGINAL ARTICLE

Authors

डॉ. संजय कुमार तिवारी
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विभाग
शा.जे.पी.वर्मा स्नाकोत्तर कला
एवं वाणिज्य महाविद्यालय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

सुषमा डहरिया
शोधार्थी
राजनीति विभाग
शा.जे.पी.वर्मा स्नाकोत्तर कला
एवं वाणिज्य महाविद्यालय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

भारत में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने में डिजिटल उपकरणों की शुरूआत एक महत्वपूर्ण कदम रही है, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर शासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिससे इन संस्थानों के कामकाज में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं । हालाँकि, इन प्रयासों की सफलता राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के समर्थन पर भी निर्भर करती है। स्मार्ट शहरों के विकास के लिए इन स्तरों पर प्रभावी नेतृत्व आवश्यक है, जो जमीनी स्तर पर शासन को और बढ़ा सकता है। डिजिटल उपकरणों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए ऐसा समर्थन आवश्यक है जो उनके प्रभाव को जमीनी स्तर पर अनुभव करने में सक्षम बनाता है । झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की ई–पंचायत पहल सफल डिजिटल उपकरण कार्यान्वयन का एक प्रमुख उदाहरण है। इस पहल ने जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल डेटा तैयार करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप इन संस्थानों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है । नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिजिटल उपकरणों ने पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर के शासन की समग्र सफलता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्य शब्द

डिजिटल उपकरण, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का महत्व, चुनौतियां.

परिचय

1992 में एक संवैधानिक संशोधन के रूप में पेश की गई पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्व–शासन को बढ़ावा देना है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, पंचायती राज संस्थानों के कामकाज में एक बड़ा बदलाव आया है। डिजिटल उपकरणों के समावेश से पंचायती राज प्रणाली की सफलता में काफी मदद मिली है। इन उपकरणों ने संचार, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी में सुधार किया

है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में अधिक प्रभावी और जवाबदेह शासन हुआ है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ–साथ पंचायती राज प्रणाली के लिए इन डिजिटल उपकरणों को अपनाना और उपयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि इसकी कार्यक्षमता को और बढ़ाया जा सके और ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में डिजिटल उपकरणों का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य नागरिक भागीदारी और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और स्थानीय सरकार स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। इसने व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है और हाशिये पर पड़े समुदायों को आवाज दी है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल उपकरणों ने सरकारी पहलों, कार्यक्रमों और अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान की है, जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। डिजिटल उपकरणों की मुख्य भूमिकाओं में से एक पंचायती राज प्रणाली के विभिन्न स्तरों के बीच संचार और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया का उपयोग करके, जानकारी को निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा आसानी से साझा और एक्सेस किया जा सकता है, जिससे बेहतर समन्वय और सहयोग हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप अंततः अधिक कुशल निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ और विकास परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन होता है। इसके अलावा, डिजिटल उपकरणों ने पंचायती राज प्रणाली के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही में भी सुधार किया है। वित्तीय प्रबंधन, परियोजना निगरानी और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार और कदाचार में काफी कमी आई है। वास्तविक समय डेटा और सूचना उपलब्धता ने परियोजना की प्रगति को ट्रैक करना, फंड उपयोग की निगरानी करना और सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना आसान बना दिया है। इससे न केवल नागरिकों का विश्वास बढ़ा है, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था की समग्र विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है। पंचायती राज प्रणाली, जो ग्रामीण भारत में शासन का एक विकेन्द्रीकृत रूप है, को डिजिटल उपकरणों के एकीकरण, इसके संचालन में क्रांति लाने और इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से बहुत फायदा हुआ है।

डिजिटल उपकरण और प्रशासनिक दक्षता

कंप्यूटर और फोन जैसे डिजिटल उपकरणों ने लोगों को शारीरिक रूप से दूर होने पर भी संचार और सहयोग करने की सुविधा प्रदान की है। आमने–सामने मिलने के बजाय, व्यक्तियों के पास संदेश भेजने या वीडियो कॉल में शामिल होने का विकल्प होता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा, डिजिटल उपकरण अत्यधिक कागजी दस्तावेज़ों की आवश्यकता को समाप्त करके संगठन को बनाए रखने में सहायता करते हैं; सभी जानकारी कंप्यूटर पर संग्रहित की जा सकती है, जिससे इसे एक्सेस करना और दूसरों के साथ साझा करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल उपकरण दस्तावेज़ों को पढ़ने और टाइप करने जैसे कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय की बचत होती है और त्रुटियाँ कम होती हैं। संक्षेप में, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता ने काम और संचार प्रक्रियाओं दोनों को काफी सरल बना दिया है, जबकि कागज के उपयोग को कम करके पर्यावरण में भी सकारात्मक योगदान दिया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

पंचायती राज प्रणाली में डिजिटल उपकरणों को शामिल करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा प्रावधान और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं जैसे कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, हितधारकों को नवीनतम जानकारी तक पहुंचने की शक्ति मिलती है। यह लेख जनता के लिए आसान सूचना पहुंच के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा देने और पंचायती राज प्रणाली के भीतर गतिविधियों की अधिक गहन जांच को सक्षम करने में डिजिटलीकरण की भूमिका पर जोर देता है।

डिजिटल इंडिया और पंचायती राज व्यवस्था

डिजिटल इंडिया और पंचायती राज व्यवस्था दो सहयोगी मित्रों के समान हैं। डिजिटल इंडिया व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं और सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का उपयोग करता है। यह बदले में पंचायती राज प्रणाली को सहायता प्रदान करता है, जो स्थानीय समुदायों को अपने विकास के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देता है। डिजिटल इंडिया पंचायतों और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों के बीच संचार की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे समुदाय के लिए सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद मिलती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप सेवाओं में सुधार, तेज़ प्रक्रियाएँ, कागजी कार्रवाई की जटिलताएँ कम हुई हैं और व्यक्तियों को समय पर सहायता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, यह भ्रष्टाचार से निपटने और धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने का कार्य करता है। डिजिटल इंडिया व्यक्तियों को प्रौद्योगिकी से परिचित कराकर और इसे उनके दैनिक जीवन में एकीकृत करके उन्हें सशक्त बनाता है। यह सक्रिय भागीदारी बेहतर निर्णय लेने और सामुदायिक सुधार को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, उद्यमशीलता प्रयासों और आर्थिक प्रगति में योगदान देता है। डिजिटल इंडिया और पंचायती राज प्रणाली दोनों ही भारत को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण घटक हैं।

पंचायती राज का महत्व

भारत में पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण समुदायों को अपनी बात कहने और ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका महत्व लोकतंत्र को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण में निहित है। पंचायती राज प्रणाली का उपयोग करके, समुदाय अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं की रणनीति बना सकते हैं और उन्हें क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह महिलाओं और निचली जाति के व्यक्तियों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में सहायता करता है। यह प्रणाली लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से, पंचायती राज यह गारंटी देता है कि ग्रामीण समुदायों को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय रूप से शामिल भी किया जाता है।

चुनौतियां और अवसर

पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण होते हैं, जिससे पंचायतों के विकास और प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समन्वय और सहयोग की यह कमी विकास परियोजनाओं और पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। पंचायतों के सामने आने वाली एक और समस्या कई राज्यों में चुनावों का असामयिक आयोजन है, जो उनके सुचारू कामकाज को बाधित करता है और अपने समुदायों की प्रभावी ढंग से सेवा करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। पंचायतों के भीतर नेतृत्व पदों पर महिलाओं की घटती शक्ति को देखना भी निराशाजनक है, क्योंकि उन्हें अक्सर अपने पुरुष रिश्तेदारों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे महिला आरक्षण का उद्देश्य कमजोर होता है और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति बाधित होती है। इसके अतिरिक्त, पंचायतें कमजोर वित्तीय आधार से जूझती हैं, सीमित धनराशि के लिए राज्य सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं, जिन्हें अक्सर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित किया जाता है, जिससे खर्च में लचीलेपन की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। पंचायतों के मामलों में क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का हस्तक्षेप भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो उनके काम और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बाधित करता है और अपने घटकों की जरूरतों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। संक्षेप में, पंचायतों को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता, समय पर कामकाज, लिंग सशक्तिकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वायत्तता और राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ सामंजस्यपूर्ण सहयोग में बाधा डालती हैं। इन स्थानीय शासी निकायों के प्रभावी प्रशासन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

डिजिटल उपकरणों के उपयोग से पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता और सफलता काफी प्रभावित हुई है। इन उपकरणों ने संचार और सूचना साझाकरण को बढ़ाया है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है और नागरिकों को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है। एक प्रमुख पहलू पंचायती राज व्यवस्था के भीतर संचार का परिवर्तन है। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की उपलब्धता के साथ, नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी त्वरित और निर्बाध रूप से संवाद कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हितधारकों को सूचनाओं का आदान–प्रदान करने, चिंता व्यक्त करने और अपडेट साझा करने, निर्णय लेने में तेजी लाने और पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, डिजिटल उपकरणों ने नागरिकों को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, नागरिक चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और नीति–निर्माण प्रक्रियाओं में योगदान कर सकते हैं, नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अंतर को पाट सकते हैं और निर्णय लेने में समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों ने ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली लागू की है, जिससे नागरिक अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए सीधे मतदान कर सकते हैं। मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है और चुनावी प्रक्रिया की सुविधा और पहुंच में वृद्धि हुई है। निष्कर्षतः, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में डिजिटल उपकरणों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इन उपकरणों ने संचार में क्रांति ला दी है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा दी है और नागरिकों को स्थानीय शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है। जैसे–जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, पंचायती राज प्रणाली के लिए अपने कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए इन डिजिटल उपकरणों को अपनाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, डिजिटल उपकरणों ने पंचायती राज प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही में काफी सुधार किया है। ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट नागरिकों को सरकारी योजनाओं, बजट और विकास परियोजनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की स्थापना की सुविधा प्रदान की है, जिससे नागरिक शिकायतों या भ्रष्टाचार के मामलों की सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार में प्रभावी रूप से कमी आई है और सिस्टम की समग्र अखंडता में वृद्धि हुई है।

संदर्भ सूची

1. हगार्गी, अम्बार्य एस. (2011) 73 अमेण्डमैण्ट एक्ट ऑफ 1992ः एन एनालेसिस, *थर्ड कॉन्सेप्ट,* वॉल्यूम 25, नं0 298, दिसम्बर 2011, पृ. 18।
2. भाग्यलक्ष्मी, जे. (1998) पंचायती राज एम्पावरिंग दॉ पीपुल्स, *योजना,* वॉल्यूम 42, नं0 7, जुलाई 1998, पृ. 21।
3. वाधवा, शालिनी (2003) *भारतीय स्थानीय प्रशासन,* अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ. 139–140।
4. उपाध्याय, देवेन्द्र (1989) *जवाहर लाल नेहरूः बहुआयामी व्यक्तित्व,* भारद्वाज पब्लिकेशन्ज, नई दिल्ली, पृ. 112।
5. सुभा, के. एवं भार्गव, बी.एस. (2000) पंचायत एण्ड एन.जी.ओ. इन स्पेशल चेन्ज, *कुरूक्षेत्र,* वॉल्यूम 48, नं0 10, जुलाई 2000, पृ. 21।
6. चांद, पी (2019) भारत में ई–गवर्नेंसः पंचायती राज संस्थानों का एक केस स्टडी, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट,* 44, पृ. 76–82।
7. शर्मा, आर. और चंदर, एम. (2020). पंचायती राज संस्थानों पर डिजिटल साक्षरता का प्रभावः हरियाणा का एक केस स्टडी, *जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट,* 39 (1), पृ. 45–62।
8. गौतम, वीर (2009) *पंचायती राज व्यवस्था,* ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 291।
9. पड़लिया, मुन्नी (2009) *भारत में पंचायती राज व्यवस्था,* (सम्पादित), अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 132।

––==00==––